



2026:AHC:128295

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 15094 / 2026

आशुतोष सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अभिषेक पांडेय, अशोक कुमार मिश्रा, शाश्वत शुक्ला

विपक्षी के अधिवक्ता : नरेंद्र शंकर, संजय पाठक, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. पुनः पुकार पर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, यद्यपि मुकदमा बाध्यकारी रूप से सूचीबद्ध है। पिछले अवसर पर, अर्थात् दिनांक 12.06.2026 को विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए थे।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 44 / 2026, अंतर्गत धारा 126(2), 190, 191(2), 191(3), 109(1), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना- किडगंज, जिला- प्रयागराज में जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को वर्तमान मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् वैभव प्रताप सिंह को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 16020 / 2026 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2026 के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 11.03.2026 से जेल में निरुद्ध है।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् वैभव प्रताप सिंह को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

7. मुकदमे के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् वैभव प्रताप सिंह को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निरस्त या स्थगित नहीं किया गया है, तथा आवेदक दिनांक 11.03.2026 से जेल में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

8. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- आशुतोष सिंह को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए:—

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआर.पी.सी. / 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा से नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / 209 बी.एन.एस. के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) वाद के उद्घाटन, (2) आरोप विरचन और (3) धारा 313 सीआर.पी.सी. के अंतर्गत कथन दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करे।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का एक आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

17 जून, 2026

कुमार मनीष

(विवेक कुमार सिंह, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"